WELT HUNGER HILFE

EUROPEAN UNION

श्रमिक संवाद

प्रवासी श्रमिकों के हितार्थ जन प्रयासों का संकलन व प्रसारण

घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS)
जगतपुर, मधुबनी

वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक–2024

स्थान : होटल गोकुल राज, मधुबनी

दिनांकः 03-05 अप्रैल, 2024

घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ, जगतपुर, मधुबनी एवं WHH EU समर्थित परियोजना IND-1389 'भारत में कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के आलोक में नागरिक सामजिक संगठनों का क्षमतावर्धन' परियोजना अंतर्गत आयोजित वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक में WHH से विजय कुमार राय (Program Manager) एवं सभी प्रोजेक्ट पाटनर्स प्रयोग, लीड्स और GPSVS के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे । इस वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक की शुरुआत श्री विजय कुमार राय, प्रोग्राम मैनेजर WHH एवं श्री रमेश कुमार, अध्यक्ष सह परियोजना निदेशक (GPSVS) ने सभी का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए समस्त संस्था प्रतिनिधिओं के साथ दीप प्रज्वलन से हुई । पहले दिन सभी प्रोजेक्ट पार्टनर्स ने अपने कार्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित किया और इस परियोजना को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर वृहत्त चर्चा की गयी ।

इसके अगले दिन फील्ड विजिट का कार्यक्रम रखा गया था । मधुबनी जिले के अन्धराठाढ़ी प्रखंड के मारन गाँव में इस परियोजना के द्वारा किये गए कार्यों एवं सकारात्मक बदलाव को एक सामुदायिक बैठक के आयोजन से किया गया जिसमें इस परियोजना के लाभार्थी (प्रवासी श्रमिक परिवार के महिला सदस्य) मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभव और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कौशल विकास प्रशिक्षण से मिल रहे लाभ एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के लिए GPSVS के द्वारा किये गए कार्यों के बारे में भी विशेष रूप से बताया । विजय कुमार राय समेत सभी प्रोजेक्ट पार्टनर्स (प्रयोग छत्तीसगढ़ एवं लीड्स झारखंड) ने समुदाय से बातचीत की एवं सबों ने जीपीएसवीएस के द्वारा किये गए कार्यों को समझा एवं सामुदायिक स्तर पर प्रभावकारी परिणाम की भरपूर सराहना भी की गई। इसके पश्चात इस वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक में शामिल तीनो संस्था के प्रतिनिधि एवं WHH से विजय राय, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), सुपौल के लिए रवाना हुए और वहां पर जीपीएसवीएस संस्था एवं आरसेटी संस्थान के आपसी सहमति, संपर्क एवं रचनात्मक समन्वय को देखकर काफी प्रभावित हुए, साथ हीं RSETI, सुपौल के निदेशक श्री धीरेन्द्र कुमार धीरज और प्रशिक्षक मुकेश कुमार मलिक से मुलाकात कर इस परियोजना में GPSVS संस्था एवं RSETI के आपसी समन्वय से प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों को दी जा रही कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में विशेष रूप से जाना और उनकी सहभागिता की सराहना भी की गई। इसी दौरान यहाँ से बकरी पालन में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं से भी मुलाकात एवं बातचीत की गयी और उनके विचारों एवं चुनौतियों तथा स्व-रोजगार की योजनाओं को समझा ।

कृषि विज्ञान केन्द्र सुखेत के वरीय वैज्ञानिक डॉ. एस.के. गंगवार एवं डॉ. राहुल सिंह के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के कृषि आधारित आजीविकामूलक कौशल विकास के विभिन्न अवसरों तथा संस्थागत समन्वय को बढ़ावा देने हेतु कार्यशाला में अपने विचार रखे। जिससे सभी प्रतिभागियों लाभान्वित हुए।

इस वार्षिक समीक्षा बैठक की सफलता के लिए सभी संस्था के प्रतिनिधियों एवं WHH के वरीय कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय कुमार राय सहित मारन गाँव के ग्रामीणों तथा RSETI सुपौल को संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

श्रमिक संवाद

प्रवेशांक: 1 मई 2024
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर

वेल्टहंगरहिल्फे एवं यूरोपियन युनियन के सहयोग से संचालित प्रवासी श्रमिक कौशल विकास कार्यक्रम के हितग्राहियों के लिए प्रकाशित

संपादक मंडलः
रमेश कुमार
जितेन्द्र कुमार
वासुदेव मंडल
अमरदेव ठाकुर

संकलन एवं प्रस्तुति
वासुदेव दास
अनिकेत नारायण
अर्चना कुमारी

सोत एवं प्रकाशक :
घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS)

ग्राफिक्स एण्ड मुद्रण :
संजीव ग्राफिक्स प्रिंटर्स एण्ड इंटरप्राईजेज
धरहराकोठी, नयाटोला, पटना-800004

केवल संस्थागत/सीमित वितरण हेतु

सम्पादकीय...

कोरोना वायरस (कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण लागू किये गये देशव्यापी लॉकडान ने भारत के उस वर्ग विशिष्ट को एक बार पुनः चर्चा में ला दिया, जो कार्य और आजीविका की तलाश में अपने गृह राज्य से बाहर रहते थे। हालांकि देश में अंतर-राज्य प्रवासियों (Inter State Migrants) का कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं है, किंतु 2011 की जनगणना एवं NSSO के सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान के अनुसार देश में 65 मिलियन अंतर-राज्य प्रवासी हैं, जिसमें 33 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक हैं। अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में देश के कुल अंतर-राज्य प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः 25 और 14 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद अन्य राज्य है। भारत में रह रहे लाखों प्रवासी कामगार हैं जो मुख्य रूप से निर्माण उद्योग, घरेलू सहायक फूटपाथ विक्रेताओं (Street Vendors) के रूप में कार्य करते हैं। जिनमें करीब एक तिहाई प्रवासी निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकांश प्रवासी श्रमिक निर्माण क्षेत्र, ईंट निर्माण उद्योग, खनन और उत्खनन उद्योग, होटल तथा रेस्तरां आदि में कार्यरत हैं। विदित हो कि ये सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। परंतु देश में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जिसके कारण इनके संबंध में आधिकारिक आँकड़े का अभाव है। भारत जैसे विशाल देश में अभी तक प्रवासी समुदाय के आकार और महत्व को सही ढ़ंग से पहचाना नहीं जा सका है। इस प्रवासी श्रमिक समुदाय के संबंध में आधिकारिक आँकड़े का अभाव इनके विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है। अधिकांश शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासियों को सुरक्षित घरों, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के अभाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई महानगरों में प्रवासी श्रमिकों की इतनी अधिक संख्या है कि इन्हें अपनी आवश्यकता तथा कार्यकुशलता के अनुरूप कार्य ही नहीं मिल पाता है और यदि कार्य मिलता भी है तो काफी कम वेतन/दैनिक मजदूरी पर, जिससे वे शोषण के लिए अभिशप्त होते रहते हैं। रोजगार की अस्थायी प्रकृति के कारण प्रवासी मजदूरों को अक्सर विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। कोविड महामारी के दौरान सोशल मिडिया ने इस मानसिकता को और बढ़ावा दिया है। सर्वप्रथम आवश्यक है कि प्रवासी श्रमिकों को भी भारतीय समाज के एक विशिष्ट हिस्से के रूप में मान्यता दी जाय और नीति निर्माण के समय प्रवासियों के मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाय। उन प्रतिबंधों को शिथिल किया जाना चाहिये जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य शहरों/महानगरों मे राशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने से वंचित करते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए देश के हर राज्य में मनरेगा, उज्ज्वला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसी उद्देश्य से बेल्टहंगरहिल्फ़े और यूरोपियन यूनियन के संयुक्त प्रयास से बिहार राज्य में घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS) के संयोजकत्व सहित छतीसगढ़ के प्रयोग और झारखंड के लीडस संस्था के द्वारा ''कोविड-19 के प्रभाव से भारत में बनी सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सामुदायिक संगठनों की क्षमता विकास कार्यक्रम'' प्रभावकारी रूप से चलाया जा रहा है।

जिसका मुख्य उद्देश्य:

- प्रवासी श्रमिकों के कौशल विकास और सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास
- उनके सार्वजनिक अधिकारों तक पहुँच, विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लाभ हेतु प्रेरित करना।
- असंगठित कामगारों के अधिकारों की वकालत/पैरवी
- कोविड के लिए जोखिम न्यूनीकरण हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन करना

उपरोक्त उद्देश्यों के आलोक में GPSVS द्वारा मधुबनी, दरभंगा और सुपौल जिले के 110 गाँवों में सघन व प्रभावकारी ढंग से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

माह अप्रैल 2024 में घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ द्वारा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यशाला का सफल आयोजन संपन्न हुआ। साथी संस्था प्रयोग एवं लीड्स के टीम एवं WHH के वरीय कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय कुमार राय के रचनात्मक उत्साहवर्धन से प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितार्थ किये जा रहे प्रयासों को एक पहचान मिली है। हम उत्तरोत्तर और अधिक गुणात्मकता से अग्रसर रहेंगे। इस न्यूजलेटर के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितार्थ किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों, सरकारी एवं अन्य हितभागियों के द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाओं को लाभ व हकदारी के लिए अभिप्रेरित करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस न्यूजलेटर के संदर्भ सामग्रियों, रिर्पोट/फोटो संकलन आदि कार्यों में तत्परता से लगे परियोजना टीम सदस्यों को धन्यवाद व शुभकानायें।

रमेश कुमार
मुख्य कार्यकारी
GPSVS

प्रवासी श्रमिक

रास्ते बड़े लंबे है,
दूर तक जाना है ।
थक गया हूं जिंदगी
थोड़ा सुस्ताने दे ।
रास्तों में पड़े पत्थर है,
और पैरों में पड़ गए छाले है ।
कैसे ठहर जाउं अब शहर में ?
रोजी रोटी पर पड़ गए जो ताले है ।
वो कहते है ,
हो गई तिजोरियां खाली ।
पर फिर भी ना जाने क्यूँ,
मेरी आशाएं और पेट रह गए खाली।
मैं तो रोज कमाता खाता था ,
मेरा साधारण बही खाता था ।
बड़े बड़े अरमानों से ,
मेरा कहा कोई नाता था ।
कभी दौड़ता सड़कों पर,
कभी कारखाने में खटता ।
कभी होटलों में खाना खिलाता,
मेरा इसी में दिन कट जाता था ।
कहते है कोई बीमारी है ,
जो आधुनिकता पर बड़ी भारी है ।
अंतरिक्ष में पहुंच गई जो ताकत है ,
वो छोटे से जीव से आज हारी है ।
मास्क दिए सैनिटाइजर दिए है ,
पर इससे मैं भूख मिटाऊ कैसे ?
रोटी की राह देखता है जो मेरा परिवार ,
उसे कल का गणित समझाऊं कैसे ?
मैं किसान भी हूं,
मै ही मजदूर भी।
मैं बैरा भी, और
मैं ही गरीब चालक भी।
मै भूखा भी हूं,
और मजबूर भी,
मै हारा भी हूं,
और हताश भी।
न जाने और कितना चलना है,
जाने कितना और लड़ना है।
थक गया हूं चलते चलते,
जिंदगी मुझे थोड़ा सा सुस्ताने दे।

अंतर्राजीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरः भर्तृहरि महताब) ने 11 फरवरी, 2021 को अंतर्राजीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों पर अपनी रिपोर्ट सौपी। कमिटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए शुरू की गई योजनाओं के असर का आकलन किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था जिसके कारण लाखों प्रवासी श्रमिक भोजन, जीविका और आश्रय के अभाव में विभिन्न राज्यों में फंस गए थे।

प्रवासी श्रमिकों की पहचानः कमिटी ने कहा कि भारत में प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए अनेक कदम उठाए गए। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैः**

1. प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा में बदलाव ताकि रोजगार के लिए स्वेच्छा से एक से दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों को इसमें शामिल किया जा सके।
2. प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए पोर्टल शुरू करना। हालांकि अंतर्राजीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या की जानकारी देने वाला कोई भरोसेमंद डेटाबेस नहीं है। इससे श्रमिकों के लिए राहत और कल्याणकारी उपायो को लागू करना मुश्किल हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों (जैसे पंजाब) में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण कुल आबंटन के लिहाज से कम हुआ। इससे लक्षित लाभार्थियों (खास तौर से प्रवासी श्रमिकों) को समय पर भोजन देने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। कमिटी ने फिर से कहा कि अंतर्राजीय प्रवासी श्रमिकों के लिए रियल टाइम भरोसेमंद डेटाबेस बनाया जाए (खास तौर से असंगठित प्रवासी श्रमिकों के लिए)।

सस्ते आवासः कमिटी ने कहा कि किफायती किराया आवासीय परिसर (एआरएचसीज) योजना में प्रवासी श्रमिक अलग से कोई श्रेणी नहीं हैं। इस योजना को इस लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है कि प्रवासी श्रमिकों को काम करने की जगह के आस-पास सस्ते किराए पर मकान उपलब्ध कराए जा सके। वर्तमान में प्रवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस) या निम्न आय वर्ग के समूह (एलआईजी) के अंतर्गत आते हैं। इसिलए प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि एआरएचसी योजना में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए।

कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि एआरएचसी योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए पारदर्शी आबंटन प्रकिया बनाई जाए। उसने यह सुझाव भी दिया कि आबंटन से संबंधित मामलों पर प्रवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरूआत की जाए।

आजीविकाः कमिटी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) वह सबसे अच्छी योजना है जो कि अदक्ष श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों सहित) को सतत् आजीविका प्रदान करती है। उसने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों द्वारा जॉब कार्ड जारी करने से पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी बनी है और यह सुनिशित हुआ है कि प्रवासी श्रमिक रोजगार से वंचित न रह जाएं । उल्लेखनीय है कि मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग करने वाले व्यक्ति के पास जॉब कार्ड होना जरूरी है।

दक्षता विकास और प्रशिक्षणः गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) छः राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के 116 चुनीन्दा जिलों में कोविड -19 महामारी के कारण वापस लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार प्रदान करता है। कमिटी ने कहा कि जीकेआरए के अंतर्गत 116 जिलों के 60 लाख प्रवासी श्रमिकों का डेटा इक्कठा किया गया। इनमे से 93 जिलों के 2.64 लाख श्रमिकों को प्रशिकक्षण के लिए चुना गया । किमटी ने सुझाव दिया कि बाकी के 23 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को चुनने की प्रकिया भी तेज की जाए ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द निरंतर काम मिल सके । कमिटी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को प्रशिकक्षण प्रदान करने में कई समस्याएं है जैसे-

(I) दक्ष श्रमिकों की मांग का कम होना,

(II) कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों का बढ़ना जिसमें दक्षता विकास का कोई प्रावधान नही है,।

(III) दक्षता की जरूरत का पता लगाने में कठिनाइयां । इसके अतिरिक्त कमिटी ने कहा कि नौकरियों की तलाश करने वाले 5.5 लाख लोगों में से 3.2 लाख को नौकरियों की पेशकश की गई। कमिटी ने सुझाव दिया कि दक्षता विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय को दक्षता विकास और गरीब लोगों (प्रवासियो सहित) का प्लेसमेन्ट सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय करने चाहिए।

परियोजना की गतिविधियाँ

यह परियोजना मधुबनी, दरभंगा और सुपौल जिलों के 18 प्रखंडों के 52 पंचायतों के 110 गाँवों में कार्यरत है । इसके अंतर्गत प्रवासी श्रमिक एवं उनके परिवारों को कोविड-19 के उचित व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जानकारी देना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और सरकारी एवं गैर सरकारी कौशल विकास केन्द्रों की आपसी सहमति, संपर्क एवं समन्वय से कौशल विकास प्रशिक्षण में नामांकन कर इन्हें प्रशिक्षण दिलाना एवं प्रशिक्षण उपरांत रोजगार व स्व-रोजगार में इनकी सहायता करना । संस्था के कार्यकर्ता इस परियोजना के चिन्हित गांवों में जाकर गाँव के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य से संपर्क स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों के साथ सामुदायिक बैठक का आयोजन करते हैं। इस सामुदायिक बैठक के दौरान उन्हें सामजिक सुरक्षा योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा जल एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं साथ हीं साथ इन योजनाओं की पात्रता, लाभ पाने की विधि एवं कौशल विकास केन्द्रों के बारे में भी बताते हैं ।

समय-समय पर सरकारी विभागों जैसे महात्मा गाँधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अफसरों से संपर्क कर उन्हें इस सामुदायिक बैठक में आने के लिए आमंत्रित करना एवं प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों को विभाग से सम्बंधित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार करने हेतु ऋण की पात्रता एवं लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराना । पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर **हेल्प डेस्क** स्थापित कर प्रवासी श्रमिक एवं उनके परिवारों की शिकायतों को पंजीकृत कर उन्हें सम्बंधित योजनाओं का यथाशीघ्र लाभ दिलवाना । ई-श्रम कार्ड, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) पंजीकरण, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि योजनाओं का लाभ दिलवाकर प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से और सबल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

क्र.सं.	जिला	प्रखंड	पंचायत	गाँव
1	मधुबनी	6	19	40
2	दरभंगा	6	11	30
3	सुपौल	6	22	40
	कुल	18	52	110

कौशल विकास प्रशिक्षण एवं उपलब्धियों की एक झलक

क्र.सं.	ट्रेड (TRADE)	पुरुष (MALE)	महिला (FEMALE)	कुल (TOTAL)
1.	बकरी पालन (Goat Rearing)	56	338	394
2.	ब्यूटिशियन (Beautician)	....	41	41
3.	डेयरी एवं वेर्मी कम्पोस्ट (Dairy & Vermin Compost)	36	17	53
4.	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट/होम हेल्थ ऐड (GDA/HHA)	25	46	71
5.	मुर्गी पालन (Poultry Farming)	01	34	35
6.	वेर्मी कम्पोस्ट (Vermin Compost)	60	104	164
7.	जैविक खाद (Organic Manure)	23	102	125
8.	अगरबत्ती निर्माण (Incence Sticks Making)	....	60	60
9.	सिलाई (Tailoring)	....	69	69
10.	राज मिस्त्री (Mason)	42	01	43
11.	व्यवसायिक जैविक खेती (Commercial Organic Farming)	15	16	31
12.	मशरुम उत्पादन (Mushroom Cultivation)	....	35	35
13.	सब्जी खेती (Vegetable Farming)	50	47	93
14.	पशुधन प्रबंधन (Livestock Management)	....	32	32
15.	मिथिला पेंटिंग (Mithila Painting)	....	51	51
16.	सॉफ्ट टॉयज मेकिंग (Soft Toys Making)	....	16	16
17.	सामान्य उद्यमिता कार्यक्रम (General EDP)	24	11	35
18.	बम्बू क्राऽट (Bamboo craft)	08	29	37
	कुल	372	1045	1489

कौशल विकास परियोजना एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

रेणु देवी (महादलित परिवार) बिहार के मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड के डुमरा एराजी गाँव की रहनेवाली हैं, उनके पति लालू सदाय जो प्रवासी श्रमिक के रूप में दुसरे राज्य में दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे थे पर कोविड-19 जैसी भयावह संक्रामक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गयी और अचानक से उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एकदम बेहाल सी हो गयी थी और परिवार का वितीय संघर्ष काफी बढ़ गया था क्योंकि इनके पति घर के अकेले ऐसे सदस्य थे जो अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर पैसा कमा रहे थे । इस दौरान इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा । इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं से एक सामुदायिक बैठक के दौरान इनसे बातचीत में इनके परिवार की यथास्थिति का पता चला । इसके तत्पश्चात संस्था के कार्यकर्ताओं ने जीविका से संपर्क स्थापित कर इनको बिहार सरकार की सात जीविकोपार्जन योजना जो की खासकर विधवा महिलाओं को स्वरोजगार एवं सशक्त बनाने के लिए आर्थिक एवं तकनीकि रूप से मदद करती है के बारे में बताया गया । इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया और जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से इनका सात जीविकोपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए अविलम्ब इनका फॉर्म भरा गया एवं विभागीय स्वीकृति के बाद इनको स्वरोजगार करने हेतु कुल 95000 रूपये दिए गए (किस्तों में) और इसकी मदद से इन्होंने खुद का एक श्रृंगार का दुकान खोला है जिससे प्रतिदिन 200-300 की आमदनी होने लगी और फिर इन्होंने बकरी पालन भी शुरु कर दिया है। इन दोनों गतिविधिओं से उनकी मासिक आमदनी 10000-15000 तक की हो जाती है। इनके परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत ही बदलाव आया है और अब ये अपने और अपने परिवार व बच्चों का जीविकोपार्जन फलस्वरूप एवं देखभाल करने में सक्षम हैं।

संघर्ष से उद्यमी बनने तक का सफर

एक संघर्षरत प्रवासी मजदूर से एक सफल बकरी पालक तक राजू साहू की यात्रा मेहनत और सच्ची लगन का एक प्रमाण है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बघाट, मनीगाछी, दरभंगा लौटने पर राजू को बेरोजगारी और वित्तीय अभाव का सामना करना पड़ा । एक सामुदायिक बैठक के दौरान उनकी मुलाकात जीपीएसभीएस, जगतपुर, मधुबनी के कार्यकर्ताओं से हुई जहाँ से उनकी पंखों को नयी उड़ान मिली ।

उन्होंने GPSVS टीम के साथ अपनी रुचि को साझा किया और फिर GPSVS टीम ने दरभंगा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) के एक विशेष (बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम) में उनका नामांकन कराया । इस कौशल विकास प्रशिक्षण ने उनकी समझ और कुशलता को एक नया आयाम दिया और इसी के फलस्वरूप राजू ने सात बकरियों से शुरुआत कर धीरे-धीरे इनकी संख्या को बढ़ाने में लगातार प्रयासरत रहे और अभी उनके पास विभिन्न प्रजातियों जैसे सिरोही, जमनापरी, बीटल, ब्लैक बंगाल, इत्यादि समेत कुल 53 बकरियाँ हैं जिनकी औसतन मूल्य लगभग ढाई से तीन लाख रूपया है ।

इन बकरियों के प्रति उनका लगाव बेहिसाब है और वे इन्हें बेटा-बेटी कहकर बुलाते हैं । जीपीएसवीएस के WHH & EU समर्थित परियोजना ''भारत में COVID-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के आलोक में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्धन'' से प्राप्त समर्थन के लिए आभारी राजू सक्रिय रूप से समुदाय को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अपनी इस कौशल का सदुपयोग करते हुए राजू समुदाय के भीतर बकरी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए दूसरों को भी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जीपीएसवीएस टीम के साथ एक अनुवर्ती बातचीत में, राजू ने प्रतिकूल परिस्थितियों से सफलता तक की अपनी यात्रा में संगठन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए ''सभी धन्यवाद जीपीएसवीएस को जाता है'' कहते हुए अपना आभार व्यक्त किया।

सफलता की कहानीः कौशल विकास प्रशिक्षण से रोजगार/स्वरोजगार को बढ़ावा

बिहार के सुपौल जिले के निर्मली प्रखंड के सिकरहट्टा गाँव के महादलित परिवार से आनेवाले गुलाब कुमार पासवान जो एक प्रवासी श्रमिक के परिवार से आते हैं और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होने के कारण इन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत कठनाइयों का सामना करना पड़ता था जानकारी और शिक्षा व कौशल के अभाव में ये अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पा रहे थे। इनके गाँव में इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संस्था कार्यकर्ताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार के बारे में प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों को अवगत कराया और इसी बैठक के दौरान गुलाब की जिज्ञासा बढ़ी और वे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो की केंद्र सरकार की एक खास योजना है जो खासकर युवाओं को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण व रोजगार देती है। इसके अंतर्गत चल रहे एडूस्पार्क ट्रेनिंग सेंटर, पटना से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण को राजी हुए और संस्था कार्यकर्ताओं ने इनका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवाया, कोर्स पूरा करने के बाद इनका जॉब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ और अभी ये दिल्ली में रहकर जॉब कर रहे हैं। 20000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अपने कमाए हुए पैसों से इन्होने अपनी बहन की शादी की है और अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह से जीविकोपार्जन एवं आर्थिक सहयोग कर रहे हैं।

सफल गतिविधियों की झलक

ब्यूटिशियन ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के बाद दरभंगा के एक ब्यूटी पार्लर में कार्यरत

जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण में नामांकन के लिए जाते प्रशिक्षु

व्यवसायिक जैविक खेती (TOT) का प्रमाण पत्र के साथ प्रवासी श्रमिक परिवार

व्यवसायिक जैविक खेती (TOT) का प्रमाण पत्र लेती हुई पुष्पा कुमारी

प्रवासी श्रमिक केन्द्रित जनजागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक बैठक

स्वरोजगार (अगरबत्ती निर्माण) कर रही सभी महिलाएँ

एक दिवसीय रोजगार मेला में प्रोत्साहन प्रमाण पत्र लेते हुए

कार्यक्रम अधिकारी श्री सुधांशु शेखर जी के द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड वितरण।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम, मधुबनी

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम, सुपौल

जैविक खेती के जरिये स्वावलंबन की राह पर महिला किसान

कपिलेश्वर साह • मधुबनी

जानकी देवी, बुधनी देवी, पूनम देवी सहित मधुबनी की 200 से अधिक महिला किसान 50 एकड़ में उन्नत खेती कर रही हैं। ये परंपरागत फसलों में करिया कामर, बकई, घुसरी, कतरनी धान के अलावा गेहूं, मडुवा, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, तोरी आदि की खेती कर रही हैं। प्रति महिला किसानों को खेती से प्रतिवर्ष 25 से 50 हजार तक की आमदनी होती है। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए फुलपरास के घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ का सहयोग मिल रहा है। महिला किसान पाठशाला और लुप्त हो रहे देसी बीज संरक्षित करने को लेकर बीज बैंक का संचालन भी चार साल से किया जा रहा है। बैंक से महिला किसानों को देसी बीज दिए जाते हैं। खेती के बाद उपलब्ध कराए गए बीज से 25 प्रतिशत अधिक बीज बैंक को वापस कर दिए जाते हैं। बीज की सुविधा और पाठशाला से किसानी के सुझाव ने महिलाओं के लिए खेती आसान बना दिया है।

राष्ट्रीय किसान दिवस

प्रति महिला किसानों को खेती से प्रतिवर्ष 25 से 50 हजार तक की होती आमदनी, रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को दिया जा रहा बढ़ावा

"जिले में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनकी सशक्तीकरण को साबित करता है। जैविक तरीके से खेती-बाड़ी किया जाना अच्छी बात है। महिला किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।"

–ललन कुमार चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी

खेती करती किसान पाठशाला की महिलाएं • जागरण

खेती के साथ-साथ वर्मी कंपोस्ट व जैविक कीटनाशक बनाने की बताई जाती विधि : महिला किसान पाठशाला जिले के घुसकीपट्टी, बालाबाखर, अमोजा, धर्मडीहा, बगहा, जहलीपट्टी, सुरियाही, भोलापुर, पथराही और दुर्गापट्टी गांवों में संचालित हो रहा है। यहां कृषि सलाहकार अजय कुमार दास के अलावा प्रशिक्षक विमल कुमार सिंह, पूनम देवी, पुष्पा कुमारी द्वारा महिला किसानों को खेती के गुर सिखाते हैं। वर्मी कंपोस्ट व जैविक कीटनाशक बनाने की विधि बताई जाती है। संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार के अनुसार पाठशाला, बीज बैंक और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर सालाना करीब पांच लाख रुपये खर्च आता है। इसका वहन खेती, जैविक खाद व कीटनाशी बिक्री और संघ के विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जाता है।

महिलाओं के परिवार के भरण-पोषण का आधार खेती-बाड़ी : किसान गौरी देवी ने बताया कि खेती ही परिवार के भरण-पोषण का आधार है। चंद्ररेखा पासवान का कहना है कि समय के बदलते परिवेश में महिलाओं के लिए कृषि कार्य काफी बेहतर साबित हो रहा है। किसान ममता कुमारी के बताया कि महिलाओं के लिए कृषि कार्य काफी लाभकारी साबित हो रहा है। संजू देवी, दुर्गा देवी, सुनैना कुमारी, रंजना कुमारी ने बताया कि कम जमीन वाली महिलाएं हरी सब्जियों का उत्पादन कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। अधिक खेत वाली महिलाएं स्वजन व मजदूरों के सहारे हरी सब्जियां, फल व गेहूं व चावल का भी खेती करती हैं। महिला किसान खेती-बाड़ी में रसायनिक खाद व कीटनाशक का उपयोग नहीं करती है। जिससे स्थानीय बाजार में इनके सब्जियों की डिमांड अधिक होती है।

जो प्रवासी श्रमिक परिवार हैं, उनको ज्यादा लाभ दिलाने का होगा काम

जीपीएसवीएस ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु खोला सहायता केंद्र

भास्कर न्यूज|झंझारपुर

अंधराठाढ़ी प्रखंड के गंधराईन चौक पर घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ जगतपुर के तत्वावधान में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक परिवारों के हित के लिए सहायता केंद्र खोला गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवश्यक कागजातों में आवासीय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड इत्यादि के लिए खोला गया है। इस कार्यक्रम को हरना पंचायत के मुखिया मोहम्मद तौवाब अंसारी, सरपंच कृष्णकांत झा एवं रखवारी पंचायत के सरपंच मुनेश्वर साफी इत्यादि के द्वारा फीता काटकर सूचना एवं जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के जिला समन्वयक शैलेंद्र कुमार कर्ण उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर परिचय के साथ सूचना जन सेवा केंद्र के उपयोगिता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। इसमें खासकर जो प्रवासी श्रमिक परिवार हैं उन परिवारों को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए संस्था प्रयासरत है। इस कार्य के लिए पंचायत के मुखिया एवं सभी प्रतिनिधियों को इस सूचना केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इसके लिए प्रचार प्रसार करने हेतु आग्रह किया। वहीं मुखिया मोहम्मद तौवाब अंसारी ने आश्वासन दिया कि यह कार्य बहुत ही सराहनीय है।

कार्यक्रम में शामिल मुखिया और अन्य प्रतिनिधि।

प्रभात खबर

प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र का किया उदघाटन

प्रतिनिधि, झंझारपुर

अनुमंडल के गंधराईन चौक पर घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ जगतपुर द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया है. हरना पंचायत के मुखिया मो. तौवाब अंसारी, सरपंच कृष्णाकांत झा एवं रखवारी पंचायत के सरपंच मुनेश्वर साफी ने केंद्र का उद्घाटन किया. गंधराईन चौक स्थित सीएससी सेंटर चला रहे विजय प्रसाद के केंद्र पर अब प्रवासी श्रमिक परिवार के हित के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवश्यक कागजात जैसे आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड की जानकारी मिलेगी. कार्यक्रम के जिला समन्वयक शैलेंद्र कुमार कर्ण जन सेवा केंद्र के उपयोगिता की जानकारी दी. जिसमें खासकर जो प्रवासी श्रमिक परिवार हैं उन परिवारों को कैसे सरकारी योजना का लाभ मिले. इसके लिए संस्था प्रयासरत है. इस कार्य के लिए पंचायत के मुखिया एवं सभी प्रतिनिधियों को इस सूचना केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले. इसके लिए प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया. मुखिया मो. तौवाब अंसारी ने आश्वासन दिया कि यह कार्य संस्था द्वारा किए जाने के लिए बहुत ही सराहनीय है. मौके पर सरपंच कृष्णाकांत झा, मुनेश्वर साफी, विकास मित्र सीताराम धांगर, सामाजिक कार्यकर्ता रामविलास धांगर, संजीत कुमार झा के अलावे कई लोग मौजूद थे.

सहायता केंद्र का शुभारंभ करते लोग।

पांच दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा

भास्कर न्यूज|झंझारपुर

घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ एवं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के संयुक्त प्रयास से प्रवासी परिवार केंद्रित पांच दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राकृतिक खेती पर आधारित है जो मारन, रखवारी में आयोजित किया किया गया। इस प्रशिक्षण की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, के वरिष्ठ वैज्ञानिक एस के गंगवार एवं वैज्ञानिक जोगेंद्र सोरेन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण को वरिष्ठ वैज्ञानिक एस के गंगवार ने प्राकृतिक खेती को अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने की सलाह दी। वैज्ञानिक जोगेंद्र सोरेन ने महिला किसानों को बताया कि प्राकृतिक खेती, कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत (जीव अमृत), घन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव अथवा सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रम्हास्त्र, अग्निअस्त्र, नीम पेस्ट, गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है।

GHOGHARDIHA PRAKHAND SWARAJYA VIKAS SANGH (GPSVS)

Head Office : Village+Post- Jagatpur, Via-Ghoghardiha, Dist-Madhubani-847402 (Bihar) INDIA

91-9431025373, 9955494453 gpsvsjp@gmail.com www.gpsvs.org